

स्टेशन, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) पर रेलवे लाइन को पार करते समय कई दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त दुर्घटनाओं को रोकने के विचार से सरकार का वहां पर ऊपरी पुल बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ।

रेलवे मन्त्री (श्री हनुमन्तभा) : (क) पिछले तीन वर्षों में 28-9-1968 को केवल एक दुर्घटना हुई जब एक भिखारिन भर्ताधिकृत रूप से गाड़ी से उतरने के प्रयास में गिर गई ।

(ख) और (ग). अभी इस स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव नहीं है ।

इस्पात का आयात तथा निर्यात मूल्य

60. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या इस्पात तथा भारी इजीनियरिंग मन्त्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को निर्यात किये जाने वाले देशी इस्पात और विदेशों से आयात किए जाने वाले इस्पात के मूल्यों के बीच बड़ा अन्तर है यद्यपि इस्पात की किस्म एक ही है, और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के निर्यात और आयात मूल्य क्या है ?

इस्पात तथा भारी इजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुहृन्मन्त शर्मा कुरेशी) : (क) और (ख). चूंकि वास्तव में निर्यात की गई श्रेणियों का कोई अधिक मात्रा में आयात नहीं किया गया है अतः कोई सार्थक तुलना करना असम्भव नहीं है । आयात किये जाने वाले इस्पात के आयात मूल्य में भाड़ा भी शामिल होता है, जो अलग-अलग देशों में अलग-अलग होता है । निर्यात में प्राप्त होने वाले शुद्ध अह्राज तक निष्पन्ना घासत मूल्य तथा बाहर के कुछ देशों द्वारा मागे गए तदनुषंगी मूल्य लगभग नीचे सारणी में दिये गये हैं :-

अप्रैल-दिसम्बर 1970 की अवधि में वास्तविक निर्यात का औसत अह्राज तक निष्पन्ना भारतीय निर्यात मूल्य

	(रुपये प्रति टन)
1. साधारण इस्पात के बिलेट	522
2. साधारण इस्पात के बार और राड	847
3. साधारण इस्पात के संरचनात्मक	1014
4. साधारण इस्पात की रेल की पट्टी	664

संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर 1970 की अवधि में औसत विदेशी मूल्य

	(रुपये प्रति टन)			
यू०के०	अमरीका	जापान	यूरोपीय संघ का बाजार	
(औसत घरेलू निर्माणी बाह्य मूल्य)			निर्माणी बाह्य औसत निर्यात मूल्य)	
1	2	3	4	
साधारण इस्पात के बिलेट	686	868	—	558

	1	2	3	4
साधारण इस्पात के बारे घौर राह	844	1,126	946	813
साधारण इस्पात के संरचनात्मक रेल की पटरियां	874	1,147	944	1,008
	858	997	—	—

रायबरेली में रूस के सहयोग से
उद्योगों की स्थापना

61. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या
औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा
करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायबरेली में
रूस के सहयोग से एक कारखाना स्थापित
किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किंग
गये करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में किसी अन्य जगह
भी रूस के सहयोग से कोई कारखाना स्थापित
करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनूल हक
चौधरी) : (क) और (ख). मे० इनसोब प्राटो
लि० कलकत्ता को उत्तर प्रदेश, रायबरेली म
वी० प्रो० प्रोमाश एक्सपोर्ट, मास्को के सहयोग
से 12,000 हल्की व्यापारिक गाड़ियां प्रतिवर्ष
बनाने की क्षमता का एक नया औद्योगिक उप-
क्रम स्थापित करने के लिए प्रासय-पत्र मंजूर
किया गया है। दोनों गैर सरकारी पार्टियों के
बीच सहयोग के व्यौरे को अभी अन्तिम रूप
दिया जाता है।

(ग) और (घ). मे० हर्ष ट्रेक्टर, नई
दिल्ली को 10,000 कृषि ट्रैक्टर (माडल टी-
25) बनाने वाली वार्षिक क्षमता वाले एक
नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना उत्तर प्रदेश
के कोनी नामक स्थान पर करने के लिए एक
औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया है। जहां
एक उत्तर प्रदेश में रूस के सहयोग से किन्हीं

अन्य प्रस्तावित कारखानों के स्थापित किए
जाने का सम्बन्ध है, उसके बारे में जानकारी
इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर
रख दी जायेगी।

Rise in Prices of Consumer Goods in
Bihar and other States

62. SHRI BHOGENDRA JHA : Will
the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP-
MENT be pleased to state :

(a) the extent of the rise in the prices
of consumer goods during the last six months
in various states and in Bihar separately ;
and

(b) the causes of this price rise and the
steps being taken to check the same ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL
DEVELOPMENT (SHRI MOINUL HAQUE
CHOUHDURY) : (a) and (b). A statement
showing the trend of retail prices of some
important consumer goods at certain centres
including Bihar State during August, 1970
to January, 1971 is laid on the Table of the
House. [Placed in Library. See No. LT—
55/71]. The statement also includes the
causes for any notable price rise during the
period.

In order to arrest any undue rise in
prices of consumer goods, various measures
are taken, such as :

- sustained efforts to step up the
production of agricultural as well
as industrial commodities to meet
the demand ; imports are also
resorted to wherever necessary ;
- building up of buffer stocks of
foodgrains etc. ;
- organisation of public distribution
system for commodities of mass
consumption like foodgrains, sugar
and milk ;
- imposition of price controls,
statutory as in the case of vanas-
pati or informal as in case of tyres